

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 13-12-25



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Saturday, 13 Dec, 2025

Edition : International Table of Contents

पेज 01 पाठ्यक्रम: जीएस 3: भारतीय अर्थव्यवस्था /	नवंबर में खुदरा मुद्रास्फीति मामूली रूप से बढ़कर 0.7% हो गई।
पेज 05 पाठ्यक्रम: जीएस 3: पर्यावरण /	यूएनईए ने जंगल की आग के प्रबंधन पर भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया
पेज 06 पाठ्यक्रम: जीएस 3: भारतीय अर्थव्यवस्था /	शुरुआत के लिए एफटीए व्यापार समझौतों से निरंतर लाभ के लिए निर्यात के लिए समर्थन आवश्यक है
पेज 06 पाठ्यक्रम: जीएस 3: भारतीय अर्थव्यवस्था /	एक आलोचनात्मक कहानी जिसे मीडिया का एक हिस्सा याद कर रहा था
पेज 09 पाठ्यक्रम : जीएस 1 : सामाजिक मुद्दे	जब शहरी विस्तार और जंगल मिलते हैं
पृष्ठ 06 : संपादकीय विश्लेषण सिलेबस : जीएस 3 : भारतीय अर्थव्यवस्था	हिंद महासागर एक नई नीली अर्थव्यवस्था के उद्गम स्थल के रूप में

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) द्वारा मापी गई भारत की खुदरा मुद्रास्फीति, अक्टूबर 2025 में 0.25% के ऐतिहासिक निचले स्तर से नवंबर 2025 में 0.7% तक बढ़ गई, जो वर्तमान CPI श्रृंखला में दूसरी सबसे कम मुद्रास्फीति रीडिंग को चिह्नित करती है। इस मामूली वृद्धि के बावजूद, वित्त वर्ष 2025-26 के पहले आठ महीनों में से सात में मुद्रास्फीति में कमी आई है, जो मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में तेज संकुचन से प्रेरित एक व्यापक-आधारित अवस्फीतिकारी प्रवृत्ति को दर्शाती है।

Retail inflation moves up marginally to 0.7% in Nov.

Inflation has slowed in seven of the first eight months of the financial year; decline in food prices offsets marginal acceleration in fuel inflation; prices in housing segment stay virtually unchanged

The Hindu Bureau
NEW DELHI

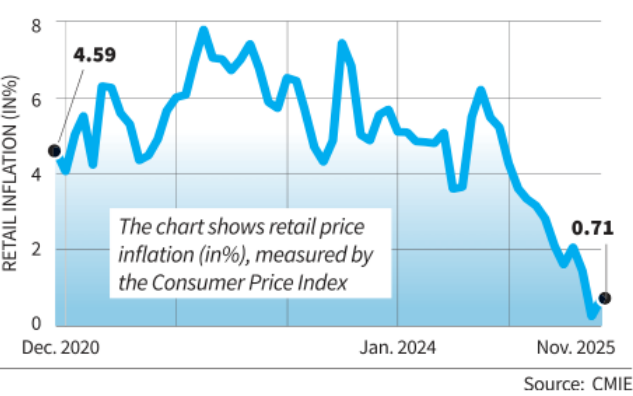
Retail inflation in India quickened marginally to 0.7% in November 2025, up from the historic low of 0.25% in October 2025, with a continued contraction in food prices offsetting a marginal acceleration in fuel inflation. November's inflation rate is the second-lowest ever recorded in the current series of the Consumer Price Index (CPI).

Inflation as measured by the CPI, for which the latest data was released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation on Friday, has slowed in seven of the first eight months of this financial year.

The food and beverages

Marginal rise

Retail inflation in India inched up in November 2025, rising from October's **record low of 0.25%**



Source: CMIE

category saw prices contract by 2.8% in November 2025, as compared to a high base of 8.2% in November of last year, and a contraction of 3.7% in October 2025.

"The factors driving inflation downwards have been the same: base effect

and decline in prices of vegetables and pulses," Madan Sabnavis, chief economist at Bank of Baroda said. "In particular, potatoes, onions and tomatoes have witnessed a decline, leading to food inflation falling by 3.9%. In the food basket, edible oils wit-

nessed sharp increases though the topline number was down to 7.9%. Mustard and coconut oil were the main drivers of inflation here."

This contraction in food prices offset the impact of a quickening in fuel inflation to 2.3% in November 2025, compared to 2% in October, and a contraction of 1.8% in November of last year. Inflation in the pan, tobacco, and intoxicants category quickened marginally in November 2025 to 3% from 2.9% in October.

The clothing and footwear category, on the other hand, saw inflation ease marginally to 1.5% from 1.7%.

Inflation in the housing category remained virtually unchanged at 2.95% in November 2025 as compared to 2.96% in October.

मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के पीछे प्रमुख चालक

एंकर के रूप में खाद्य मूल्य अपस्फीति

- खाद्य और पेय पदार्थों की श्रेणी में 2.8% की गिरावट आई, जो अक्टूबर में देखी गई अपस्फीति प्रवृत्ति को जारी रखती है।
- प्रमुख योगदानकर्ता सब्जियों और दालों, विशेष रूप से आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में गिरावट कर रहे थे।

- एक मजबूत आधार प्रभाव (पिछले साल नवंबर में 8.2% पर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति) ने स्पष्ट मॉडरेशन को बढ़ाया।
- हालांकि, खाद्य तेल चिंता का क्षेत्र बना रहा, मुद्रास्फीति 7.9% पर रही, जो सरसों और नारियल तेल द्वारा संचालित है, जो आपूर्ति-पक्ष की कमजोरियों को उजागर करती है।

ईंधन मुद्रास्फीति में मध्यम वृद्धि

- ईंधन और प्रकाश मुद्रास्फीति अक्टूबर में 2% से बढ़कर 2.3% हो गई।
- यह ऊर्जा लागत और वैश्विक ईंधन मूल्य गतिशीलता के क्रमिक पास-थ्रू को दर्शाता है, हालांकि स्तर अपेक्षाकृत सौम्य रहते हैं।

कोर और अन्य घटक

- आवास मुद्रास्फीति लगभग 2.95% पर अपरिवर्तित रही, जो किराये और आवास की लागत में स्थिरता का संकेत देती है।
- कपड़ों और जूतों की मुद्रास्फीति में थोड़ी कमी आई, जिससे मांग पक्ष के दबाव में कमी आई।
- पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों में मामूली वृद्धि देखी गई, जो काफी हद तक कराधान और प्रशासित कीमतों से प्रभावित थी।

व्यापक आर्थिक और नीतिगत निहितार्थ

- मौद्रिक नीति स्थान: लगातार कम हेडलाइन मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को विकास को प्राथमिकता देने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करती है, हालांकि खाद्य या ईंधन की कीमतों में अचानक उलटफेर के खिलाफ सतर्कता की आवश्यकता होती है।
- ग्रामीण-शहरी गतिशीलता: खाद्य अपस्फीति से उपभोक्ताओं, विशेष रूप से शहरी गरीबों को लाभ होता है, लेकिन कृषि आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे ग्रामीण मांग के लिए चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।
- आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन: सब्जियों की गिरती कीमतों और खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों के बीच का अंतर कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं, आयात विविधीकरण और घरेलू तिलहन उत्पादन में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- मुद्रास्फीति की गुणवत्ता: वर्तमान मॉडरेशन गहरी संरचनात्मक अवस्फीति के बजाय आधार प्रभावों और अस्थिर खाद्य पदार्थों से अधिक प्रेरित है, जिसके लिए सतर्क व्याख्या की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

नवंबर 2025 में रिटेल इन्फ्लेशन में 0.7% तक की मार्जिनल वृद्धि भारत में सौम्य मुद्रास्फीति की स्थितियों की व्यापक कथा को नहीं बदलती है। खाद्य मूल्य अपस्फीति प्राथमिक स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करना जारी रखती है, जो ईंधन से हल्के दबावों को दूर करती है और गैर-खाद्य वस्तुओं का चयन करती है। नीति निर्माताओं के लिए, चुनौती किसानों की आय को कम किए बिना मूल्य स्थिरता बनाए रखने में है, जबकि विकास का समर्थन करने और संरचनात्मक आपूर्ति-पक्ष की कमजोरियों को दूर करने के लिए मुद्रास्फीति खिड़की का उपयोग करना है। मध्यम अवधि में, टिकाऊ मुद्रास्फीति नियंत्रण आधार प्रभावों पर कम और उत्पादकता लाभ, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और संतुलित मांग पुनरुद्धार पर अधिक निर्भर करेगा।

यूपीएससी प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नवंबर 2025 में CPI मुद्रास्फीति वर्तमान CPI श्रृंखला की शुरुआत के बाद से दूसरी सबसे कम थी.
2. खाद्य कीमतों में संकुचन नवंबर 2025 में समग्र मुद्रास्फीति को कम करने वाला प्राथमिक कारक था.
3. नवंबर 2025 में ईंधन मुद्रास्फीति संकुचनात्मक (नकारात्मक) क्षेत्र में रही।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: b)

यूपीएससी मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न: भारत में खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर 2025 में ईंधन की कीमतों में मामूली तेजी के बावजूद असाधारण रूप से कम रही। इस प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार कारकों पर चर्चा करें और मौद्रिक नीति और आर्थिक विकास के लिए इसके निहितार्थों की जांच करें। **(150 शब्द)**

पृष्ठ 05 : जीएस 3 : पर्यावरण

नैरोबी में आयोजित 7वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA-7) में, "जंगल की आग के वैश्विक प्रबंधन को मजबूत करना" शीर्षक से भारत के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से अपनाया गया था। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण राजनयिक और पर्यावरणीय उपलब्धि है, क्योंकि प्रस्ताव में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, जोखिम मूल्यांकन और तैयारियों पर जोर देने के साथ प्रतिक्रियाशील अग्निशमन से सक्रिय जंगल की आग की रोकथाम के लिए वैश्विक बदलाव का आह्वान किया गया है। यह कदम जलवायु परिवर्तन, भूमि-उपयोग परिवर्तन और पारिस्थितिक क्षरण के कारण दुनिया भर में बड़े पैमाने पर जंगल की आग में वृद्धि के बीच आया है।

भारत के प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं**प्रतिमान बदलाव: प्रतिक्रिया से रोकथाम तक**

- संकल्प पारंपरिक अग्निशमन-केंद्रित दृष्टिकोणों की सीमाओं पर प्रकाश डालता है।
- यह रोकथाम, तैयारी और लचीलापन-निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अग्रिम शासन की वकालत करता है।

प्रारंभिक चेतावनी तंत्र

- उपग्रह-आधारित निगरानी, जलवायु पूर्वानुमान और वास्तविक समय डेटा साझाकरण को मजबूत करना।
- आग के जोखिमों की भविष्यवाणी करने के लिए मौसम संबंधी डेटा, वनस्पति तनाव संकेतक और मानव गतिविधि पैटर्न का एकीकरण।

बेहतर जोखिम मूल्यांकन

- अग्नि-प्रवण क्षेत्रों, विशेष रूप से जंगलों, घास के मैदानों और पीटलैंड के वैज्ञानिक मानचित्रण का आह्वान किया।
- जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान और सामाजिक-आर्थिक कारकों पर विचार करते हुए भेद्यता आकलन पर जोर दिया

INBRIEF

UNEA adopts India's proposal on wildfire management

India's push for a stronger global system to manage and prevent wildfires – centred on early-warning mechanisms and improved risk assessments – was formally adopted on Thursday at the United Nations Environment Assembly (UNEA-7) in Nairobi, the Environment Ministry said in a statement. India's resolution, titled "Strengthening the Global Management of Wildfires," calls for a shift from reactive firefighting to proactive prevention. Officials said these measures are essential to address what India called the "cascading ecological, economic and social impacts" of today's fires.

व्यापक प्रभावों को संबोधित करना

- मानता है कि जंगल की आग के बहुआयामी परिणाम होते हैं:
- पारिस्थितिक: जैव विविधता का नुकसान, वन क्षरण, कार्बन उत्सर्जन।
- आर्थिक: आजीविका, कृषि और बुनियादी ढांचे को नुकसान।
- सामाजिक: समुदायों का विस्थापन, वायु प्रदूषण के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव।

वैश्विक सहयोग और क्षमता निर्माण

- विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ज्ञान-साझाकरण और समर्थन को प्रोत्साहित करता है।
- दक्षिण-दक्षिण सहयोग के साथ संरेखित करता है, जहां भारत खुद को एक ज्ञान और प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में रखता है।

भारत के लिए महत्व

- जलवायु नेतृत्व: वैश्विक पर्यावरण शासन में एक मानदंड निर्धारक के रूप में भारत की भूमिका को सुदृढ़ करता है, न कि केवल एक नियम-लेने वाले के रूप में।
- घरेलू प्रासंगिकता: भारत को अक्सर हिमालयी राज्यों, मध्य भारत और पश्चिमी घाट में जंगल की आग का सामना करना पड़ता है, जिससे वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं सीधे लागू होती हैं।

राष्ट्रीय पहलों के साथ संरेखण:

- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी)
- जंगल की आग की रोकथाम और प्रबंधन योजना
- इसरो उपग्रह डेटा और भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) आग अलर्ट का उपयोग
- ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव: विकासशील देशों पर जलवायु-प्रेरित आपदाओं के असंगत प्रभावों पर प्रकाश डालता है।

व्यापक वैश्विक संदर्भ

- ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भूमध्यसागरीय, अमेज़न और बोरियल जंगलों में जंगल की आग की तीव्रता बढ़ रही है।
- जंगल की आग वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभर रही है, जो जलवायु परिवर्तन के साथ एक फीडबैक लूप बना रही है।
- यूएनईए को अपनाने से यह बढ़ती मान्यता का संकेत मिलता है कि जंगल की आग स्थानीय आपदाएं नहीं बल्कि वैश्विक पर्यावरणीय जोखिम हैं।

निष्कर्ष

यूएनईए-7 में भारत के जंगल की आग प्रबंधन प्रस्ताव को अपनाना वैश्विक पर्यावरणीय सोच में एक रणनीतिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो संकट प्रतिक्रिया से लेकर जोखिम की रोकथाम तक है। पूर्व चेतावनी प्रणालियों, वैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाकर, भारत ने एक दूरदर्शी और जलवायु-लचीले वैश्विक ढांचे को आकार देने में योगदान दिया है। आगे बढ़ते हुए, इस संकल्प की प्रभावशीलता कार्रवाई योग्य राष्ट्रीय नीतियों, वित्तपोषण तंत्र और तकनीकी सहयोग में इसके अनुवाद पर निर्भर करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि जंगल की आग का शासन जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न बढ़ते जोखिमों के साथ तालमेल बनाए रखता है।

यूपीएससी प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

प्रश्न : संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनईए) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यूएनईए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर पर्यावरण मामलों पर सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है।
2. UNEA की बैठक द्विवार्षिक रूप से होती है और इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है।
3. संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश समान मतदान अधिकार के साथ यूएनईए के सदस्य हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) 1, 2 और 3
- (d) केवल 1 और 3

उत्तर : (c)

यूपीएससी मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न : जंगल की आग एक शासन चुनौती पेश करती है जो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण और आजीविका में कटौती करती है। भारत और वैश्विक संदर्भ के संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए।

पृष्ठ 06 : जीएस 3 : भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत का मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का बढ़ता नेटवर्क वैश्विक व्यापार प्रणाली के साथ इसके बढ़ते जुड़ाव को दर्शाता है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, भारत ने 20 क्षेत्रीय या मुक्त व्यापार समझौतों में प्रवेश किया है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ हाल के समझौते और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा और एसएसीयू जैसे प्रमुख भागीदारों के साथ चल रही बातचीत शामिल है। हालांकि, पहले के एफटीए के अनुभव से संकेत मिलता है कि केवल व्यापार समझौते निर्यात आधारित विकास की गारंटी नहीं देते हैं; उन्हें घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता और रणनीतिक नीति समर्थन द्वारा पूरक किया जाना चाहिए।

भारत के एफटीए के मिश्रित परिणाम

बढ़ता व्यापार घाटा

- आसियान, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भारत के एफटीए के परिणामस्वरूप व्यापार घाटा बढ़ गया है।
- आसियान व्यापार घाटा लगभग 10 बिलियन डॉलर (2017) से बढ़कर लगभग 44 बिलियन डॉलर (2023) हो गया।
- जापान के साथ, पूंजी और प्रौद्योगिकी-गहन वस्तुओं के आयात ने भारत की निर्यात वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है।

संरचनात्मक और नीतिगत बाधाएं

- गैर-टैरिफ बाधाओं जैसे मानकों, प्रमाणन और पारस्परिक मान्यता समझौतों पर अपर्याप्त बातचीत।
- उत्पत्ति के नियमों का कमजोर प्रवर्तन, तीसरे देश के सामानों को एफटीए भागीदारों के माध्यम से प्रवेश करने की अनुमति देता है।
- एफटीए भारत की क्षेत्रीय ताकत (श्रम-गहन विनिर्माण, सेवाओं) के साथ पर्याप्त रूप से संरेखित नहीं थे।
- सीमित हितधारक परामर्श और एफटीए प्रावधानों का खराब घरेलू प्रसार, जिससे भारतीय फर्मों द्वारा उपयोग कम हो गया।

पाठ्यक्रम सुधार के संकेत

- आसियान, जापान और कोरिया के साथ मौजूदा एफटीए की समीक्षा से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं।
- भारत-यूई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) अधिक संतुलित परिणाम दिखाता है:
- वित्त वर्ष 2025 में गैर-तेल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो व्यापार उदारीकरण और निर्यात क्षमता के बीच बेहतर संरेखण का संकेत देता है।
- यह सामान्य टैरिफ में कमी के बजाय अनुकूलित, ब्याज-आधारित व्यापार समझौतों की ओर बदलाव को दर्शाता है।
- चल रही बातचीत के लिए निहितार्थ

FTAs for a start

Support for exports is a must for sustained gains from trade pacts

According to the World Trade Organization, India has entered into 20 regional or free trade agreements (FTAs). This count excludes the most recent pacts signed with the United Kingdom in July and with the European Free Trade Association (EFTA), which came into effect in October. Also under way are negotiations, most notably with the United States, the European Union, Canada and the Southern African Customs Union. With India now facing American tariffs of up to 50% on key exports, there are intensive efforts to fast-track these agreements. Some reports have even suggested discussions around a re-engagement with the Regional Comprehensive Economic Partnership, which India walked away from in 2019 over concerns related to farm sectors and rules of origin. However, New Delhi has not accepted accession; at most, it has explored consultative channels. Yet, trade diversification demands far more – a deep, deliberate transformation of the country's productive sectors and integration into global value chains.

Commerce Ministry data show that some earlier FTAs – with ASEAN, Japan and South Korea – have tilted the trade balance sharply against India. The trade deficit with ASEAN widened from about \$10 billion in 2017 to nearly \$44 billion by 2023. A similar pattern holds for Japan – despite India's exports rising, imports of high-value, capital-intensive goods have grown even faster. The reasons are structural and policy-driven. While FTAs opened the door, mutual recognition arrangements on quality standards, certifications, rules of origin and other non-tariff barriers were not adequately negotiated. Many FTAs were not custom-designed to reflect India's sectoral strengths, nor were consultations with industry bodies sufficiently robust. The government did too little to popularise these agreements domestically, even as partner economies made full use of the preferential margins. A review of the ASEAN, Japan and Korea FTAs has brought some course correction. This is reflected in the more balanced outcomes under the India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement – non-oil trade touched about \$100 billion in FY25 (DGFT data). As India accelerates negotiations with the EU and the U.S., it must internalise these lessons. In the case of the U.S., consultations with services, seafood, engineering goods and textiles exporters must shape India's negotiating stance. With the EU, the focus must be on carbon-intensive sectors such as iron and steel and cement, especially given the Carbon Border Adjustment Mechanism. A trade agreement is only the beginning. The arduous task of supporting India's exporters – through standards, infrastructure, technology and market intelligence – must follow if these pacts are to deliver lasting gains.

संयुक्त राज्य

- भारतीय निर्यात पर बढ़ते टैरिफ (50% तक) ने तात्कालिकता बढ़ा दी है।
- बातचीत को क्षेत्र-विशिष्ट परामर्श द्वारा आकार दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से:
- सेवाएं
- समुद्री खाद्य
- इंजीनियरिंग सामान
- कपड़ा

यूरोपीय संघ

- लोहा और इस्पात और सीमेंट जैसे कार्बन-गहन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें।
- संक्रमणकालीन व्यवस्था, प्रौद्योगिकी सहयोग और जलवायु वित्त के माध्यम से कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना।

RCEP री-एंगेजमेंट डिबेट

- हालांकि भारत आरसीईपी में फिर से शामिल होने के लिए सहमत नहीं हुआ है, लेकिन खोजपूर्ण परामर्श बाजार पहुंच और घरेलू क्षेत्र की सुरक्षा, विशेष रूप से कृषि और एमएसएमई के बीच तनाव को उजागर करता है।
- एफटीए से परे: क्या आवश्यक है?
- पैमाने, प्रौद्योगिकी और रसद सुधारों के माध्यम से वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में एकीकरण।

निर्यात समर्थन में:

- गुणवत्ता और मानकों का अनुपालन
- व्यापार बुनियादी ढांचा और रसद
- बाजार खुफिया और निर्यात ऋण
- पीएलआई योजनाओं और कौशल पहल सहित व्यापार नीति और औद्योगिक नीति के बीच अधिक समन्वय।

निष्कर्ष

एफटीए भारत के व्यापार परिवर्तन के लिए एक आवश्यक लेकिन अपर्याप्त शर्त है। पिछले अनुभव से पता चलता है कि संरचनात्मक बाधाओं को दूर किए बिना, भारत निर्यात लाभ के बिना आयात में वृद्धि का जोखिम उठाता है। जैसे-जैसे भारत उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ बातचीत में तेजी ला रहा है, इसलिए जोर केवल समझौतों पर हस्ताक्षर करने से हटकर घरेलू निर्यात क्षमता बनाने, गैर-टैरिफ विषयों पर बातचीत करने और जमीनी स्तर पर फर्मों का समर्थन करने पर केंद्रित होना चाहिए। केवल तभी एफटीए निरंतर, समावेशी और लचीले व्यापार-आधारित विकास में तब्दील हो सकते हैं।

यूपीएससी प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. विश्व व्यापार संगठन के रिकॉर्ड के अनुसार भारत ने 20 से अधिक क्षेत्रीय या मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।
2. भारत-आसियान एफटीए के कार्यान्वयन के बाद आसियान के साथ भारत का व्यापार घाटा काफी बढ़ गया है।
3. भारत के सभी एफटीए के परिणामस्वरूप टैरिफ उदारीकरण के कारण व्यापार का अनुकूल संतुलन हुआ है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर : a)

यूपीएससी मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न: मुक्त व्यापार समझौते केवल व्यापार एकीकरण का शुरुआती बिंदु हैं, अंतिम गंतव्य नहीं। एफटीए के साथ भारत के अनुभव के संदर्भ में इस कथन की आलोचनात्मक जांच करें।

पृष्ठ 06 : जीएस 3 : भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत के तिमाही 2 के राष्ट्रीय खातों के आंकड़ों की हालिया जारी, जिसमें 8.2% की मजबूत जीडीपी वृद्धि दर्शाई गई है, एक कम चर्चा वाली लेकिन महत्वपूर्ण विकास के साथ मेल खाती है: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत के राष्ट्रीय खातों के आंकड़ों को 'सी' ग्रेड प्रदान किया, जो इसके मूल्यांकन ढांचे में दूसरा सबसे कम है। जबकि हेडलाइन विकास के आंकड़ों ने आशावाद पैदा किया, आईएमएफ की कार्यप्रणाली विश्वसनीयता के बारे में चिंताओं, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र का अनुमान लगाने में, मीडिया का न्यूनतम ध्यान आकर्षित किया। यह आर्थिक शासन, डेटा विश्वसनीयता और सूचित सार्वजनिक चर्चा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है।

A critical story that a chunk of the media missed

The release of the national accounts data for Quarter 2 recently was also one that coincided with serious concerns being expressed by the International Monetary Fund (IMF) about the way India calculates its data. In fact, the IMF has given India's national accounts statistics, which includes Gross Domestic Product and Gross Value Added, a C grade, which is the second lowest grade. While Q2 produced 8.2% growth – much more than expected – very few would be aware of the IMF's concerns.

This is because the media virtually ignored what the IMF had to say. Only one daily, *The Hindu*, reported it and made it a front page story ("IMF gives 'C' grade for India's national accounts statistics", November 28, 2025), but the pink papers, which should have been the most interested in this report, ignored it to a large extent. When some of these newspapers decided that it was worth publishing, they did so, but only in the inside pages, which was bizarre and perplexing.

An issue

The truth is that the IMF's grading of India's national accounts statistics is a matter of concern and a key part of that is how we calculate GDP.

India uses the formal organised sector as a proxy for calculating growth in the informal unorganised sector. But the unorganised sector, even after excluding agriculture, is still 30% of GDP. So the first question is this: do we really have a reliable and accurate way of estimating



Karan Thapar is a television anchor

The International Monetary Fund's grading of India's national accounts statistics is a matter of concern

growth in this sizeable sector or is it just an intelligent guesstimate?

'A less than reliable method'

Pronab Sen, the former Chief Statistician, and Arun Kumar, a former professor of economics at Jawaharlal Nehru University – the economists this writer spoke to – believe that this is "a less than reliable method".

Their concern needs explanation. When you use the organised sector as a proxy for calculating the unorganised sector, the assumption made is that they have both moved in the same direction. But when there is a crisis or an unusual development, that may not be the case. And that is exactly what happened when India went through demonetisation, the introduction of Goods and Services Tax (GST) and the COVID-19 pandemic. These events have meant that India's organised and unorganised sectors have not been in kilter. They have moved in different directions.

While the organised sector expanded on all three occasions, the unorganised sector went into decline. So, during these years, using the organised sector as a proxy for calculating the unorganised sector meant that we were overestimating the performance of the unorganised sector.

What does this mean about India's quarterly estimates? It must be remembered that what made the media euphoric was the quarterly estimate of 8.2% growth. Professor Sen's statement must be brought in at this point: "For

the quarterly GDP estimates we make a lot of assumptions. We simply don't have quarterly data for most things. Now[,] when we don't have the data you have to go by assumptions. You look at past relationships, past trends and try to do the best you can. But until we get to a situation where most of the data that we need for quarterly estimations are actually corrected physically[,] this problem is not going to get solved."

The answer is blunt

This leads to another conclusion. The concern that the IMF has expressed, and which underlies the lowly 'C' grade, is not going to be hastily resolved. There is no doubt that the Union Ministry of Statistics and Programme Implementation is working on updating the GDP base year and methodology of calculation and hopes to release the new series next year, probably by the end of February. But the question is this: how much improvement will we see in the way the unorganised sector is estimated? When asked if India can adequately resolve the IMF's concern, Prof. Sen's answer was short and blunt: "I don't think we can."

All this has been mentioned because we rely on the media to inform us and, usually, to help us analyse and understand. But if the media ignores critical stories, it leaves us not just uninformed but also unable to fully understand what has happened. It also means that journalists are not doing their job. That is a sorry outcome for all of us.

आईएमएफ द्वारा उजागर किए गए मुख्य मुद्दे

जीडीपी आकलन में पद्धतिगत कमजोरी

- भारत संगठित क्षेत्र को प्रॉक्सी के रूप में उपयोग करके असंगठित (अनौपचारिक) क्षेत्र के विकास का अनुमान लगाता है - जो सकल घरेलू उत्पाद (कृषि को छोड़कर) का लगभग 30% है।
- यह दृष्टिकोण मानता है कि दोनों क्षेत्र एक साथ चलते हैं, एक धारणा जो सामान्य समय में हो सकती है लेकिन संरचनात्मक झटके के दौरान विफल हो जाती है।

आर्थिक झटकों के दौरान विचलन

- नोटबंदी (2016), जीएसटी रोलआउट और कोविड-19 महामारी जैसी घटनाओं ने इस कल्पित संरेखण को बाधित कर दिया।
- साक्ष्य बताते हैं कि संगठित क्षेत्र का विस्तार हुआ या तेजी से सुधार हुआ, असंगठित क्षेत्र सिकुड़ गया या पिछड़ गया, जिससे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का संभावित अधिक अनुमान लगा।

त्रैमासिक डेटा बाधाएँ

- जैसा कि पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद प्रणब सेन ने रेखांकित किया है, भारत में कई क्षेत्रों के लिए व्यापक उच्च-आवृत्ति (त्रैमासिक) डेटा का अभाव है।
- नतीजतन, त्रैमासिक जीडीपी अनुमान मान्यताओं, एक्सट्रपलेशन और पिछले रुझानों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, जिससे सटीकता और मजबूती कम हो जाती है।

आईएमएफ का 'सी' ग्रेड: यह क्या दर्शाता है

- ग्रेड डेटा कवरेज, समयबद्धता, स्थिरता और विश्वसनीयता पर चिंताओं को दर्शाता है, जरूरी नहीं कि इरादा या अखंडता हो।
- यह संकेत देता है कि भारत की सांख्यिकीय प्रणाली कार्यात्मक है, लेकिन यह सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं से कम है, विशेष रूप से एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के लिए।

नीति और शासन निहितार्थ

- आर्थिक डेटा की विश्वसनीयता: विश्वसनीय जीडीपी डेटा मौद्रिक नीति, राजकोषीय योजना, निवेशकों के विश्वास और वैश्विक विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है।
- आधार-वर्ष संशोधन की सीमाएं: जबकि सरकार जीडीपी आधार वर्ष और कार्यप्रणाली को अपडेट करने की योजना बना रही है, विशेषज्ञों को इस बात पर संदेह है कि क्या यह अनौपचारिक क्षेत्र माप अंतराल को पर्याप्त रूप से हल करेगा।

सांख्यिकीय सुधारों की आवश्यकता:

- उद्यम सर्वेक्षण और श्रम बल डेटा को मजबूत करना
- डिजिटल लेनदेन डेटा, जीएसटी एनालिटिक्स और प्रशासनिक डेटाबेस का लाभ उठाना
- राज्य-स्तरीय और क्षेत्र-विशिष्ट उच्च-आवृत्ति संकेतकों में सुधार

मीडिया की भूमिका और लोकतांत्रिक जवाबदेही

- मुख्यधारा के मीडिया कवरेज से इस मुद्दे की लगभग अनुपस्थिति चयनात्मक रिपोर्टिंग के बारे में एक व्यापक चिंता को उजागर करती है।
- लोकतंत्र में, मीडिया जटिल डेटा और सार्वजनिक समझ के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।
- हेडलाइन ग्रोथ के आंकड़ों को बढ़ाते हुए पद्धतिगत चिंताओं को नजरअंदाज करने से एकतरफा कथा बनाने का जोखिम होता है, जिससे सूचित बहस और जवाबदेही कम हो जाती है।

निष्कर्ष

भारत के राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों के लिए आईएमएफ का 'सी' ग्रेड एक बड़ी, विविध और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को मापने में एक संरचनात्मक चुनौती को रेखांकित करता है, खासकर व्यवधान की अवधि के दौरान। हालांकि हेडलाइन जीडीपी वृद्धि के आंकड़े प्रभावशाली लग सकते हैं, लेकिन उनके पद्धतिगत आधार जांच की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं के लिए, प्राथमिकता गहन सांख्यिकीय सुधारों में निहित है, न कि केवल आवधिक आधार-वर्ष संशोधन। समान रूप से, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, मीडिया को इस तरह के घटनाक्रमों के साथ गंभीर रूप से जुड़ना चाहिए। सतत आर्थिक नीति निर्माण न

केवल विकास परिणामों पर निर्भर करता है, बल्कि उन्हें रिपोर्ट करने वाले डेटा की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और अखंडता पर भी निर्भर करता है।

यूपीएससी प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

प्रश्न : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आईएमएफ अपने डेटा गुणवत्ता मूल्यांकन ढांचे (डीक्यूएफ) के तहत अपने सदस्य देशों के राष्ट्रीय खातों के डेटा की गुणवत्ता का आकलन करता है।
2. आईएमएफ द्वारा निर्दिष्ट 'सी' ग्रेड डेटा की विश्वसनीयता और पद्धतिगत मजबूती के बारे में गंभीर चिंताओं का तात्पर्य है।
3. भारत मुख्य रूप से प्रत्यक्ष, उच्च-आवृत्ति उद्यम-स्तरीय डेटा का उपयोग करके सकल घरेलू उत्पाद में असंगठित क्षेत्र के योगदान का अनुमान लगाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर : a)

यूपीएससी मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न: आर्थिक आंकड़ों की सार्वजनिक समझ को आकार देने में मीडिया की भूमिका की गंभीर जांच करें। लोकतांत्रिक जवाबदेही और आर्थिक नीति निर्माण के लिए चयनात्मक रिपोर्टिंग के निहितार्थ क्या हैं?

समाचार में मुख्य मुद्दों पर प्रकाश डाला गया

तेजी से शहरीकरण और पर्यावास विखंडन

- निर्मित क्षेत्रों, मेट्रो निर्माण, सड़कों और रियल एस्टेट परियोजनाओं के विस्तार ने जंगलों, घास के मैदानों और आर्द्रभूमि को खंडित कर दिया है।
- बेंगलुरु का निर्मित क्षेत्र तीन दशकों में दोगुना से अधिक हो गया है, जबकि वृक्षों के आवरण और आर्द्रभूमि में तेजी से गिरावट आई है।
- शहर का लगभग 87% परिदृश्य पक्का है, जिससे पारिस्थितिक तनाव बढ़ गया है।

बढ़ता मानव-वन्यजीव संघर्ष

- तेंदुओं, हाथी, चित्तीदार हिरणों, सांपों और पक्षियों के साथ मुठभेड़ में वृद्धि।
- बेंगलुरु के बाहरी इलाके में अनुमानित 80-85 तेंदुए हैं, जो इसे सबसे अधिक फ्री-रेंजिंग बिग कैट वाली मेट्रो बनाता है।
- फसल के छापे, संपत्ति की क्षति, चोटें और कभी-कभी मानव मृत्यु बफर जोन प्रबंधन में शासन अंतराल को दर्शाती है।

मांजा (ग्लास-कोटेड पतंग स्ट्रिंग) एक शहरी खतरे के रूप में

- एक प्रमुख मानवजनित खतरा जो पक्षियों, विशेष रूप से काली पतंगों को बड़े पैमाने पर चोट पहुंचाता है।
- वन्यजीव प्रजनन चक्रों के साथ प्रतिच्छेद करने वाली मौसमी सांस्कृतिक प्रथाओं ने मृत्यु दर को बढ़ा दिया है।

बुनियादी ढांचे-प्रेरित वन्यजीव चोटें

- कांच की इमारतों, वाहनों और बिजली लाइनों के साथ टकराव प्रवासी और निवासी पक्षियों को तेजी से प्रभावित करते हैं।
- शहरी डिजाइन पारिस्थितिक आंदोलन पैटर्न के प्रति काफी हद तक असंवेदनशील रहता है।

संस्थागत और नियामक अंतराल

- बत्रेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) का कमजोर प्रवर्तन।
- ईएसजेड अधिसूचना के बावजूद जोनल मास्टर प्लान का अभाव।
- बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं वन्यजीव गलियारों को खंडित करती हैं, परिदृश्य-स्तर के संरक्षण को कमजोर करती हैं।

व्यापक पारिस्थितिक और शासन महत्व

- शहरी पारिस्थितिकी परिप्रेक्ष्य: शहर पारिस्थितिक शून्य नहीं हैं, बल्कि जटिल पारिस्थितिक तंत्र हैं जो विविध जीवों का समर्थन करते हैं, धूर्तों और उभयचरों से लेकर बड़े मांसाहारियों तक।
- जलवायु परिवर्तन संबंध: आवास तनाव, पानी की कमी और बढ़ता तापमान वन्यजीव विस्थापन को तेज करते हैं।
- वनों से परे जैव विविधता संरक्षण: शहरी हरित स्थानों, आर्द्रभूमियों, संस्थागत परिसरों और पारिस्थितिक गलियारों के महत्व पर प्रकाश डालता है।

- दोधारी तलवार के रूप में जन जागरूकता: बेहतर रिपोर्टिंग तंत्र बचाव संख्या को बढ़ाता है, लेकिन पारिस्थितिक व्यवधान के पैमाने को भी प्रकट करता है।

आगे की राह: नीति और योजना अनिवार्यता

- एकीकृत शहरी नियोजन: मास्टर प्लान में जैव विविधता-संवेदनशील डिजाइन, वन्यजीव गलियारों और बफर जोन को शामिल करें।
- ESZ शासन को मजबूत करें: नियमित ऑडिट, सख्त प्रवर्तन और सामुदायिक भागीदारी।
- शहरी डिजाइन सुधार: पक्षी-सुरक्षित ग्लास, कम रात की रोशनी, ग्रीन जोन के पास यातायात शांत।
- व्यवहारिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप: मांजा का विनियमन, सह-अस्तित्व पर जन जागरूकता।
- विकेंद्रीकरण और भीड़भाड़ कम करना: क्षेत्रीय विकास के माध्यम से मेगासिटी पर दबाव कम करना।

निष्कर्ष

बेंगलुरु का मामला एक व्यापक राष्ट्रीय चुनौती को दर्शाता है: भारत के शहर अपने पारिस्थितिक शासन ढांचे की तुलना में तेजी से विस्तार कर रहे हैं। शहरीकरण, अपरिहार्य होने के बावजूद, पारिस्थितिक रूप से विनाशकारी होने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्यों और वन्यजीवों के बीच बढ़ता इंटरफ़ेस शहरों को साझा आवासों के रूप में फिर से कल्पना करने की तत्काल आवश्यकता का संकेत देता है, न कि विशेष रूप से मानव डोमेन के रूप में। टिकाऊ शहरी वायदा योजना पर निर्भर करेगा जो बुनियादी ढांचे के साथ-साथ पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता को महत्व देता है, सह-अस्तित्व को बाद के विचार के बजाय विकास के मूल सिद्धांत के रूप में एम्बेड करता है।

यूपीएससी मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न : अनियोजित शहरी विस्तार पारिस्थितिक परिदृश्य को कैसे बदलता है? आसपास के संरक्षित क्षेत्रों के साथ बेंगलुरु की बातचीत के उदाहरण का उपयोग करके अपना उत्तर स्पष्ट करें। (150 शब्द)

The Indian Ocean as cradle of a new blue economy

When the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) was negotiated in the 1970s and early 1980s, India

stood with the world's smallest and most vulnerable states. Alongside Pacific Island countries, India championed the principle that the seabed beyond national jurisdiction should be the "common heritage of mankind". It was a remarkable moment: a large developing country aligning itself with island nations, not for advantage, but for fairness.

This was not new for India. As early as the 1950s, Jawaharlal Nehru recognised the ocean's centrality to India's future, declaring: "Whichever way we turn, we are drawn to the seas. Our future security and prosperity are closely linked with the freedom and the resources of the oceans." That foresight set the stage for India's enduring role as both a maritime nation and a maritime leader. Half a century later, the ocean faces pressures unimaginable at the time of UNCLOS. Climate change is heating and acidifying the seas, sea levels are rising, and illegal and unregulated fishing is stripping marine life from the water column.

The Indian Ocean, home to one-third of humanity, is already one of the most climate-vulnerable basins on earth.

India now has both the opportunity and the responsibility to play a historic leadership role once again. This time, the task is not to draft law, but to shape practice – ensuring that the Indian Ocean becomes not a theatre of rivalry, but a laboratory of sustainability, innovation, and resilience.

The case for a Blue Ocean strategy

India's Blue Ocean Strategy should rest on three pillars: stewardship of the commons, resilience, and inclusive growth.

First, stewardship. India must continue to assert that the Indian Ocean is a shared space, not a contested one. By prioritising ecosystem restoration, biodiversity protection, and sustainable fisheries, India can set the tone for cooperative management, rather than competitive exploitation.

Second, resilience. As the climate crisis intensifies, ocean nations must focus on adaptation and preparedness. India can lead by establishing a Regional Resilience and Ocean Innovation hub – one that strengthens ocean observation networks, improves early warning systems, and transfer technology to small island developing states and African coastal nations.

Third, inclusive growth. The Indian Ocean must become a driver of prosperity for all littoral states. Green shipping, offshore renewable energy, sustainable aquaculture, and marine



Kilaparti Ramakrishna

is the Director of Marine Policy Centre and Senior Adviser to the President on Ocean and Climate Policy at the Woods Hole Oceanographic Institution, the world's largest independent oceanographic institution at Woods Hole, Massachusetts, U.S.

biotechnology offer pathways to development that are compatible with climate goals. Realising this potential, however, will require sustained investment and coordinated regional action.

It is encouraging that the financial tide is beginning to turn. At the Blue Economy and Finance Forum (BEFF) held in Monaco, in June 2025, governments, development banks and private investors highlighted a €25 billion pipeline of existing ocean investments and announced €8.7 billion in new commitments, with near-parity between public and private sources. The Finance in Common Ocean Coalition, bringing together 20 public development banks, announced annual pledges of \$7.5 billion, while the Development Bank of Latin America doubled its blue economy target to \$2.5 billion by 2030.

At COP30 in Belém, the Brazilian Presidency launched the One Ocean Partnership as part of the Belém Action Agenda, committing to mobilise \$20 billion for ocean action by 2030. These signals matter. They demonstrate that the ocean – long marginal in climate finance – is now firmly on the global agenda.

India must seize this moment to channel global financing into regional priorities. An Indian Ocean Blue Fund, seeded by India and open to contributions from development banks, philanthropy, and the private sector, could provide the institutional architecture needed to turn pledges into projects.

Security through sustainability

Much of today's discourse on the Indian Ocean is framed in terms of "Indo-Pacific strategy", naval balance, freedom of navigation, and secure sea lanes. These concerns are legitimate. But they should not obscure a more fundamental reality: ocean insecurity begins with ecosystem collapse and climate disruption.

Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, coral reef degradation and intensifying storm surges erode livelihoods and undermine social stability. Addressing these threats requires a shift from traditional notions of maritime security toward security through sustainability.

India's doctrine of Security and Growth for All in the Region (SAGAR) articulated by Prime Minister Narendra Modi in Mauritius in 2015, offers an important anchor. "We seek a future for the Indian Ocean that lives up to its name as a zone of peace, stability and prosperity," he said.

The Indian Navy and the Indian Coast Guard, working alongside civilian agencies, can deepen regional cooperation in maritime domain awareness, disaster response and ecosystem monitoring - aligning security objectives with environmental stewardship. Equally important is the story India chooses to tell. Not of rivalry, but

of responsibility. Not of dominance, but of stewardship. As External Affairs Minister S. Jaishankar has noted, India's approach to the Indian Ocean is "cooperative, consultative, and outcome-oriented," aimed at shared prosperity and stability.

The guiding principle should be simple and resonant: "From the Indian Ocean, for the World."

India's historic responsibility

At the Stockholm Conference in 1972, Prime Minister Indira Gandhi warned, "We do not want to impoverish the environment any more than we want to impoverish our people." That insight remains strikingly relevant.

COP30 in Belém (2025) and the G-20 Summit in Johannesburg recognised the importance of terrestrial and marine ecosystems for climate stability, sustainable development, and community resilience as well as anchoring scaling up of finance and support for developing countries, aligning with the equity dimensions of ocean action.

Momentum is building. With the outcomes of the 3rd United Nations Ocean Conference (UNOC3) in Nice, COP30 in Belém, and the entry into force of the Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) Agreement, 2026 is shaping up to be a pivotal year for ocean governance. India's readiness to ratify the BBNJ Agreement presents an opportunity to demonstrate how the Indian Ocean region can pioneer globally relevant solutions, from green shipping corridors and blue bonds to inclusive marine technology transfer and carefully governed ocean-based carbon dioxide removal. This agenda could also serve as a defining theme for India's chairmanship of the Indian Ocean Rim Association.

India's history in ocean diplomacy gives it credibility. India's future in ocean leadership gives it the responsibility. The Indian Ocean, the cradle of some of the world's oldest civilisations, can now become the cradle of a new blue economy, one that marries prosperity with sustainability, and resilience with justice.

The challenge is clear: to move beyond rhetoric, to align vision with finance, and to build partnerships that endure. For the world, the message is urgent: the ocean is not a void to be filled or a frontier to be conquered. It is the foundation of life itself.

If India leads with ambition, humility, and inclusivity, the Indian Ocean can once again demonstrate what was evident during UNCLOS negotiations: that even in the most complex of arenas, cooperation can prevail over conflict, and solidarity over rivalry.

The time to act is now.

India must take the lead in promoting the guiding principle, 'From the Indian Ocean, for the World'

GS 3 : भारतीय अर्थव्यवस्था

UPSC Mains Practice Question : हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को अब पारिस्थितिक स्थिरता से अलग नहीं किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन, अवैध, गैर-रिपोर्टेड और अनियमित (IUU) मछली पकड़ने और भारत के SAGAR सिद्धांत के आलोक में इस कथन पर चर्चा करें। (250 शब्द)

संदर्भ :

यह लेख एक नई, टिकाऊ नीली अर्थव्यवस्था की नींव के रूप में हिंद महासागर के भविष्य को आकार देने में भारत की उभरती भूमिका पर प्रकाश डालता है। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) की वार्ता के दौरान भारत के ऐतिहासिक नेतृत्व और "मानव जाति की साझी विरासत" के रूप में महासागर की सैद्धांतिक वकालत के दौरान भारत के ऐतिहासिक नेतृत्व से प्रेरणा लेते हुए, लेख में तर्क दिया गया है कि भारत आज एक नई जिम्मेदारी का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, महासागर क्षरण और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज होने के साथ, हिंद महासागर - मानवता के एक तिहाई का घर - वैश्विक स्थिरता, लचीलापन और इकटिती बहस का केंद्र बन गया है।

मुख्य तर्क और विश्लेषण**1. कानूनी नेतृत्व से व्यावहारिक नेतृत्व तक**

- यूएनसीएलओएस के दौरान, भारत ने मानदंडों और सिद्धांतों को आकार दिया; आज, चुनौती कार्यान्वयन और व्यवहार है।
- हिंद महासागर को केवल रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता का रंगमंच नहीं बनना चाहिए, बल्कि स्थायी शासन, नवाचार और सहयोग के लिए एक प्रयोगशाला बनना चाहिए।

2. ब्लू इकोनॉमी रणनीति: तीन स्तंभ

- लेख में एक सुसंगत भारतीय नीले महासागर रणनीति का प्रस्ताव है :

कॉमन्स का प्रबंधन

- पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, जैव विविधता संरक्षण और टिकाऊ मत्स्य पालन पर जोर।
- एकतरफा शोषण का मुकाबला करते हुए हिंद महासागर के एक साझा स्थान के रूप में विचार को पुष्ट करता है।

लचीलापन

- जलवायु परिवर्तन ने हिंद महासागर को सबसे कमजोर क्षेत्रों में से एक बना दिया है।
- छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (एसआईडीएस) और अफ्रीकी तटीय देशों को प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, महासागर अवलोकन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक क्षेत्रीय लचीलापन और महासागर नवाचार केंद्र का प्रस्ताव।

समावेशी विकास

- ब्लू इकोनॉमी क्षेत्र जैसे ग्रीन शिपिंग, अपतटीय नवीकरणीय, टिकाऊ जलीय कृषि और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी।
- विकास न्यायसंगत होना चाहिए, जिससे सभी तटीय राज्यों को लाभ हो, न कि केवल प्रमुख शक्तियां।

3. लापता कड़ी के रूप में वित्त

- लेख एक महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित करता है: महासागर अंततः जलवायु वित्त मुख्यधारा में प्रवेश कर रहे हैं।

प्रमुख वैश्विक घटनाक्रम:

- ब्लू इकोनॉमी एंड फाइनेंस फोरम (मोनाको, 2025): €25 बिलियन की निवेश पाइपलाइन।
- कॉमन ओशन गठबंधन में वित्त: \$7.5 बिलियन वार्षिक प्रतिबद्धताएं।
- COP30 (बेलेम): 2030 तक 20 बिलियन डॉलर के लक्ष्य के साथ एक महासागर साझेदारी।

- भारत के लिए, यह इसके लिए जगह खोलता है:
- एक हिंद महासागर ब्लू फंड, जिसे भारत द्वारा स्थापित किया गया है और विकास बैंकों, परोपकार और निजी पूंजी द्वारा समर्थित किया गया है।
- वैश्विक प्रतिज्ञाओं को क्षेत्रीय, कार्रवाई योग्य परियोजनाओं में अनुवादित करना।

4. समुद्री सुरक्षा को फिर से परिभाषित करना

- पारंपरिक प्रवचन नौसैनिक शक्ति, समुद्री मार्गों और भारत-प्रशांत भू-राजनीति पर केंद्रित है।
- लेख सुरक्षा को "स्थिरता के माध्यम से सुरक्षा" के रूप में फिर से परिभाषित करता है:
- अवैध, गैर-रिपोर्टेड और अनियमित (IUU) मछली पकड़ने, प्रवाल भित्तियों का नुकसान, और जलवायु-प्रेरित आपदाओं जैसे खतरे आजीविका और सामाजिक स्थिरता को कमजोर करते हैं।
- भारत के सागर सिद्धांत (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) के अनुरूप है।

भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल की भूमिका:

- समुद्री डोमेन जागरूकता, आपदा प्रतिक्रिया, पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी।
- रणनीतिक सुरक्षा के साथ पर्यावरण प्रबंधन का एकीकरण।

5. बहुपक्षीय गति और भारत का अवसर

- आगामी और हाल के मील के पथर:
- यूएनओसी3 (अच्छा)
- COP30 (बेलेम)
- बीबीएनजे समझौते के लागू होने का प्रवेश

भारत के संभावित नेतृत्व क्षेत्र:

- बीबीएनजे का अनुसमर्थन और कार्यान्वयन।
- ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर, ब्लू बॉन्ड, समुद्री प्रौद्योगिकी हस्तांतरण।
- सावधानीपूर्वक नियंत्रित महासागर-आधारित कार्बन डाइऑक्साइड हटाने।
- हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) एक प्रमुख संस्थागत मंच के रूप में काम कर सकता है।

निष्कर्ष

लेख एक सम्मोहक मामला बनाता है कि हिंद महासागर एक नई नीली अर्थव्यवस्था का उद्गम स्थल बन सकता है, जैसे कि इसने कभी प्राचीन सभ्यताओं का पोषण किया था। महासागर कूटनीति में भारत की ऐतिहासिक विश्वसनीयता, वर्तमान भू-राजनीतिक महत्व के साथ मिलकर, महत्वाकांक्षा, समावेशिता और संयम के साथ नेतृत्व करने की एक अनूठी जिम्मेदारी डालती है। बयानबाजी से आगे बढ़ने के लिए वित्त के साथ दृष्टिकोण, स्थिरता के साथ सुरक्षा और वैश्विक समानता के साथ राष्ट्रीय हित को संरेखित करने की आवश्यकता होगी। यदि भारत सफल होता है, तो हिंद महासागर एक बार फिर यह प्रदर्शित कर सकता है कि सहयोग संघर्ष पर हावी हो सकता है - और यह समृद्धि ग्रह की कीमत पर नहीं आने की आवश्यकता है।